(ङ) निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद बैश्य): (क) से (ङ) मौजूदा नीति के अनुसार लोहे और इस्पात का निर्यात निर्बाध रूप से किया जा सकता है। लोहे और इस्पात का निर्यात और वह स्थान, जहां निर्यात किया जाना है, अनेक घटकों जैसे घरेलू और अन्तर्राष्ट्रीय मांग, घरेलू मूल्य, आयातकर्त्ता देशों में इस्पात के मूल्य इत्यादि पर निर्भर करता है। ये घटक समान्यत: परिवर्तनशील हैं और बार-बार बदलते रहते हैं। मौजूदा बाजार परिस्थितियों के आधार पर उद्यमी स्वयं ही निर्यात-बाजार तलाश करते हैं और निर्यात करते हैं।

इस्पात मंत्रालय ने लोहे और इस्पात के निर्यात के संबंध में एक विशेषज्ञ दल गठित किया था जिसने हाल ही में प्रस्तुत की गई अपनी रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ यह सुझाव दिया है कि भारतीय इस्पात उत्पादकों को तेजी से बढ़ रहे दक्षिण-पूर्व एशियाई, पूर्वी एशियाई और चीन के बाजारों पर ध्यान देना चाहिए। इस रिपोर्ट में जापान, अमरीका, पश्चिमी यूरोप और पूर्वी यूरोप में अवसरों के बारे में भी उल्लेख किया गया है और यह सुझाव दिया गया है कि पाकिस्तान को निर्यात करने के अतिरिक्त बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार आदि जैसे अन्य पड़ौसी देशों में बाजार दृढ़ करने के प्रयास करने चाहिए।

निर्यात करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों में निम्नलिखित उपाय करना शामिल हैं:—

(i) विनियम की बाजार दर पर निर्यात से हुई आय की पूर्ण परिवर्तनीयता,

(ii) अग्रिम लाइसेंसिंग योजना के तहत् निर्यातकों को अपनी आवश्यकता का कच्चा माल शुल्क मुक्त मंगाने की सुविधा उपलब्ध कराना,

(iii) निर्यात किए जाने वाले सामान के निर्माण में प्रयुक्त होने वाले किसी आयातित अथवा उत्पाद शुल्क वाले माल पर दिए गए शुल्क की वापसी, और

(iv) धारा 80 एच० एच० सी० के तहत् निर्यात से हुई आय पर आयकर से छूट।

SAIL Unit in Assam

999. DR. MOHAN BABU: Will the Minister of STEEL be pleased to state:

(a) whether SAIL has planned to set up a unit in Assam;

(b) if so, the details thereof including the investment to be made and production capacity; and

(c) by when the project is likely to start?

THE MINISTER OF STEEL AND MINISTER OF MINES (SHRI BIRENDRA PRASAD BAISHYA): (a) and (b) A Galvanising unit with a production capacity of 40,000 tonnes per annum of corrugated/plain sheets with an investment of around Rs. 42.85 crores has been planned to be set up by Steel Authority of India Limited (SAIL) in Assam.

(c) The work on the Project is in hand of SAIL.

Equity participation by SAIL in Australian Company

1000. SHRI AMAR SINGH: Will the Minister of STEEL be pleased to state:

(a) whether Government are aware that the Steel Authority of India propose to acquire 14.8% stake in an Australian Company that mines coking coal;

(b) if so, the details thereof; and

(c) if so, the reasons that weighed with the Steel Authority of India for diversifying its activities in out sourcing the inputs instead of sticking to its core competence?

THE MINISTER OF STEEL AND MINISTER OF MINES (SHRI BIRENDRA PRASAD BAISHYA): (a) It will not be in commercial interest of SAIL to disclose any details of the proposal as it is at a very preliminary stage and SAIL is subjected to secrecy obligations in this regard.

(b) and (c) Do not arise in view of (a) above.

Use of new Steel Technology to reduce Coal consumption

1001. SHRI YERRA NARAYANA-SWAMY: Will the Minister of STEEL be pleased to state:

(a) whether there is a proposal to obtain new steel technology by SAIL from Japan to reduce coal consumption;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether it is a fact that SAIL plants are using obsolete equipment and technical skills;